AIDWA

नवंबर न्यूज लेटर

अनुक्रमणिका

- संपादकीय
- “तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं...” गीत की लेखिका, कमला भसीन, नहीं रही - मनजीत राठी
- लखीमपुर खीरीरू जघन्य नरसंहार - मधु गर्ग
- विश्व गुरू बनने चले देश के स्कूलों में शिक्षक नहीं कक्षायें भी नहीं - संध्या षैली
- कोरोना वैक्सीन कैम्प की आवश्यकता और उसके अनुभव - नीलम तिवारी
- भाजपा शासित असम सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की शैतानी साजिश

संपादकीय

इस अंक के संपादकीय मे सिर्फ भाजपा और संघ परिवार के घिनौने चेहरे के पर्दाफाश करने की कोशिश ही की जा सकती है। उसकी हिंसात्मक हरकतें, उसके नफरत फैलाने की गतिविधियां, उसकी प्रजातन्त्र का गला घोटने के प्रयास, उसकी महिला-विरोधी और दलित-विरोधी मानसिकता और अल्प-संख्यकों के प्रति उसके घृणा, इन सबकी अनेकों उदाहरण हमारे सामने पिछले कई वर्षों से हम सबके सामने हैं। लेकिन, पिछले दिनों मे उत्तर प्रदेश और असम मे हमें जो देखने को मिला, वह तो उसकी अमानवीय हैवानियत और रक्त पिपासा के डरावने प्रमाण हैं।

3 अक्तूबर को – गांधी जयंती के बस एक दिन के बाद – लखीमपुर खेरी मे, दिन दहाड़े, पूरी दुनिया को साक्षी बनाते हुए, भाजपा के केंद्रीय नेता, राज ग्रह मंत्री, अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के पुत्र, आशीष मिश्रा 'मोनु', ने एक नया हथियार ईजाद कर डाला। उन्होने अपनी जीप को प्रदर्शन से लौट रहे शांतिपूर्ण किसानों के ऊपर चढ़ाकर, चार किसानों की हत्या कर डाली और न जाने कितनों को घायल कर दिया। वहीं खड़े एक स्थानीय पत्रकार, रमन कश्यप, भी वहीं मारे गए। मोनु के वाहन और उनके साथ आए लोगों मे तीन और लोग मारे गए।

मोनु के पिता टेनी क्षेत्र के सांसद हैं जो हाल मे ही उत्तर प्रदेश मे चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लुभाने के लिए केंद्रीय गृह राज मंत्री बनाए गए हैं, ने कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र मे प्रदर्शन कर रहे किसानों से कह डाला था की उनको वह कुछ मिनटों मे ही ठीक करना जानते हैं। इसकी प्रतिकृया किसानों की ओर से तब हुई जब 3 अक्तूबर को उनके पैतृक गाँव मे होने वाले वार्षिक दंगल के मौके पर अतिथि के रूप मे पधारने वाले उ प्र के उप मुख्य मंत्री, मौर्य, के हेलीकाप्टर को उतरने से उन्होने सफलतापूर्वक रोक दिया। इसके बाद वे लौट रहे थे जब टेनी पुत्र ने अपनी जीप द्वारा उन पर खूनी हमला कर डाला।

इस घटना के खिलाफ, देश भर मे तेज़ प्रतिरोध हुआ लेकिन कई दिनों तक मोनू को स्थानीय पुलिस बचाती रही। यह तो उत्तर प्रदेश का अब जाना माना रवैया ही बन गया है। एक तरफ शक के आधार पर अल्पसंख्यकों और दलितों को पुलिस की गोली का निशाना बड़ी आसानी से बना दिया जाता है और दूसरी ओर, भाजपा के करीबियों को जो जघन्य अपराधों मे लिप्त पाये जाते हैं, उन्हे बचाने मे पूरी ताकत लगा दी जाती है। किसानों के तीव्र विरोध के सामने, उ प्र के प्रशासन को भी झुकना पड़ा और मोनु जेल भेज दिये गए लेकिन उनके पिता को इस बात के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है की वे अपने पद का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने के लिए करें।

लखीमपर खीरी के वह दृश्य : खून से लथ-पथ किसानों की लाशें, किसी भयानक जानवर जैसे उन पर चढ़ रही वह जीप, उनके घर की रोती-बिलखती महिलाएं और किसानो और आम लोगो का उबलता आक्रोश, यह सब हमारे मस्तिष्क पर गुदे हुए हैं, मिटेंगे नहीं।

असम मे हुई भाजपाई बर्बरता की तस्वीरें तो और भी ज़्यादा मार्मिक और परेशान करने वाली हैं। राज्य की भाजपा सरकार, विधान सभा चुनाव जीतने के बाद, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध आग उगलने मे लगी है। उन्हे 'घुसपैठिया' करार देकर, उन्हे जानवरों की तरह इधर से उधर हाँकने का अभियान उसने शुरू कर दिया है। 23 सितंबर को, दरंग ज़िले के गोरुखूटी गाँव मे वहाँ पर दशकों से बसे, खेती करने वाले मुस्लिम परिवारों पर पुलिस-प्रशासन ने हल्ला बोल दिया और उन्हे ज़बरदस्ती वहाँ से खदेड़ने की कोशिश की। जब किसानों ने विरोध किया, तो पुलिस ने गोली चला दी और एक युवक और एक बच्चा वहीं मर गए। बेरहमी की इंतेहा तो तब देखने को मिली जब सरकारी फोटोग्राफर ने गोली खाये युवक के शरीर पर कूदना शुरू कर दिया, उसको लातों से मारा और उसकी गर्दन को अपने जूतों तले रौंदा।
स्तब्ध कर देने वाली इन तसवीरों को देखकर भी बहुतों के दिल नहीं पसीजे। यह है संघ परिवार के ध्रुवीकरण के अभियान का नतीजा। उसने देशवासियों के बड़े हिस्से को अपनी तरह अमानवीय बनाने मे काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है। असम और देश के तमाम लोग जानते हैं, की दरंग मे खेती करने वाले भारत के नागरिक हैं, उन्हे वहाँ रहने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन फिर भी वे चुप्पी साधे हुए हैं।

अपने आंदोलन को ज़िंदा रखने के लिए, हमे संघ परिवार के ध्रुवीकरण के खूनी अभियान को समझना होगा। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत पैदा करके, उनकी तमाम संघर्ष करने वाले मजदूर-किसानों पर आक्रमण करने की क्षमता बढ़ती है। दरंग की घटनाओं पर हमारी चुप्पी, लखीमपुर खीरी की हिंसा करने की हिम्मत संघ परिवार के सदस्यों मे पैदा करती है।

यह सराहनीय है की दरंग और लखीमपुर खीरी हमारी असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश की एडवा की बहने पहुंची। उन्होने पीड़ित परिवारों के साथ अपने आपको जोड़ा और हमारे संगठन ने पूरे देश की महिलाओं के बीच संघ परिवार के असली एजेंडे का प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। यही हमारे अपने संघर्ष की धार को ज़ंग खाने से बचाने का रास्ता है।

सुभाषिणी अली

"तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं..." गीत की लेखिका, कमला भसीन, नहीं रही

– मनजीत राठी

गत 25 सितंबर को मशहूर कवि, लेखिका तथा नारीवादी कार्यकर्ता, कमला भसीन का 75 वर्ष की उम्र में निधन, देश भर में महिला आंदोलन के लिए भारी क्षति है। वे पिछले कुछ समय से दिल्ली के एक हस्पताल मे कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। वे लैंगिक समानता, शिक्षा, गरीबी-उन्मूलन, मानवाधिकार और दक्षिण एशिया में शांति जैसे मुद्दों पर 1970 से लगातार सक्रिय थीं। उन्होनें दक्षिण एशियाई देशों में नारीवादी आंदोलन को गति प्रदान करने मे भी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वे सबसे ज्यादा अपने लिखे गीतों और कविताओं के माध्यम से जानी जाती है जो साक्षरता आंदोलन, महिला आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन के तहत नीचे जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरीय सम्मेलनों व सभाओं मे बहुत चाव से गाए जाते हैं। "मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है" और "तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं" द ऐसे ही कुछ यादगार गीत और कविताएं हैं। कमला भसीन कई औरतों के संगठनों , जैसे 'सहेली' 'जागो री' और 'वन बिलियन राइजिंग' आदि से सक्रिय रूप से जुड़ी थीं और 1984 मे स्थापित 'जागोरी" महिला रिसोर्स केंद्र की संस्थापक सदस्य थी। उनकी पहचान नारीवादी सिद्धांतों को जमीनी कोशिशों से मिलाने वाले दक्षिण एशियाई नेटवर्क 'संगत' के संस्थापक के तौर पर भी है, जिसे उन्होंने साल 2002 में शुरू किया था और जो ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की वंचित महिलाओं के लिए काम करता है। उन्होंने नारीवाद और पितृसत्ता को समझने की दिशा में कई किताबें भी लिखी है जो अनेक भाषाओं मे अनुवादित हुई हैं। काली फॉर विमेन द्वारा प्रकाशित उनकी किताब "पितृसत्ता क्या है" (1993) कई विश्व-विध्यालयों मे एम ए के विधयार्थियों को पढ़ाई जाती है।

कमला भसीन का जन्म 1946 में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हुआ था। वे ख़ुद को 'आधी रात की संतान' कहती थीं, यानि विभाजन की त्रासदी के दौरान पैदा हुई भारतीय उपमहाद्वीप की पीढ़ी। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली थी और पश्चिमी जर्मनी के मंस्टर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट की पढ़ाई की. 1976-2001 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ काम किया. इसके बाद उन्होंने ख़ुद को पूरी तरह से 'संगत' के कामों और जमीनी संघर्षों के लिए समर्पित कर दिया। औरतों की आजादी से जुड़ा उनका ये नारा - श्मेरी बहनें मांगे आजादी, मेरी बेटी मांगे आजादी, मेरी अम्मी मांगे आजादी, भूख से मांगे आजादीश्, कार्यकर्ताओं मे खूब लोकप्रिय हआ। कमला भसीन को जीवन में कई निजी आघात भी लगे, लेकिन वे सामाजिक कार्य की अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ती रहीं। उनकी 27 साल की इतिहासकार पुत्री नीतो, जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उनका आकस्मिक निधन एक बड़ी त्रासदी थीं। उनका पुत्र बचपन में टीका लगने के बाद हुए रियक्शन के कारण सेरीबरल पालसी (मश्तिष्क पक्षाघात) का शिकार बना और पूरी तरह से देखभाल कर्ताओं पर निर्भर है। मगर पारिवारिक मसलों के कारण उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और अंत तक सक्रिय रहीं। 1917 में दिए एक साक्षात्कार में कमला भसीन में कहा था कि पुरुषों को यह समझना होगा कि पितृसत्ता किस तरह उनका अमानवीकरण (डिह्यूमनाइज) कर रही है. जैसे, उदाहरण के लिए, पितृसत्ता उन्हें रोने की इजाजत नहीं देती. उन्होंने अपना इमोशनल इंटेलीजेंस खो दिया है। वे ख़ुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते। उन्होंने कई बार विभिन्न मंचों पर महिलाओं के बलात्कार को लेकर प्रयुक्त होने वाली शब्दावली पर भी सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि जब बलात्कार होता है 'तब इज्जत मर्द की लुटती है औरत की नहीं।' हालांकि हाथरस बलात्कार मामले मे और सामान्य तौर पर भी महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार पर बात करते हुए वे जातिय दृष्टिकोण को सम्मिलित करना आवश्यक नही समझती थी, जबकि श्रेणियों में बंटे हमारे समाज में जातिगत हिंसा के विशेष स्वरूप और दलित महिलाओं से जुड़े विशिष्ट पहलूओँ को नकारा नही जा सकता है। तीसरे जेंडर के मुद्दों, तकलीफों व अनुभवों को नारीवाद के दायरे मे शामिल करने की दिशा मे भी उनके वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन पितृसत्ता के खिलाफ व्यापक लड़ाई में उनके योगदान को नकारा नही जा सकता।

कमला भसीन के निधन पर महिला कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्हे करीब से जानने वाली नारीवादी कार्यकर्ता, कविता श्रीवास्तव ने लिखा, "हमारी प्रिय कमला भसीन के गुजरने पर पूरी तरह हैरान और दुखी हूं. उम्मीद बांटने, अपने गीतों और दोस्ती में वे कितनी उदार थीं. उनके पास ये विशेष प्रतिभा थी, सोच बदलने की और वे नारीवादी विमर्श को इतनी सामान्य भाषा में समझाती थीं कि एक बच्चा भी समझ ले. रत्ती भर भी घमंड नहीं, हमेशा आलोचना को स्वीकारने और उसके अनुरूप ढलने को तैयार रहती थींश्" अभिनेत्री और कार्यकर्ता शबाना आजमी ने उन्हें याद करते हुए लिखा, "मुझे हमेशा लगता था कि कमला भसीन को कोई हरा नहीं सकता और वे आखिर तक ऐसी ही रहींश्. हम एक्शनएड के लोग और वे हजारों, जिनके जीवन को उन्होंने संवारा, उनके बिना और गरीब हो जाएंगे.." मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) के संस्थापक निखिल दे के अनुसाररू "साहसी कमला भसीन ने अपनी आखिरी लड़ाई भी हंसते हुए और एक अच्छी गुजरी जिंदगी का जश्न मनाते हुए लड़ी....उनकी हिम्मत, उनकी हंसी, उनके गीत और उनकी अद्भुत ताकत उनकी विरासत हैं." इतिहासकार एस. इरफान हबीब ने भी भसीन के गुजरने पर शोक जाहिर किया हैरू "प्रिय

दोस्त और एक विलक्षण इंसान कमला भसीन के निधन पर बहुत दुख हुआ...आप बेहद याद आएंगी."। केंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद जीवन के अंतिम दौर में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अस्पताल के गंभीर माहौल में भी अपने गानों, दोहों और कविताओं के दम पर ऊर्जा का संचार किया। उनके अंतिम संस्कार पर दिल्ली के विभिन्न कोनों से शामिल उनकी 'सहेलियों' ने, मुनासिब तौर पर, उनके द्वारा लिखे गीत गा कर उन्हे अंतिम विदाई दी।

लखीमपुर खीरी - जघन्य नरसंहार
अंहकारी सत्ता के पहियों तले कुचलता लोकतंत्र..

— मधु गर्ग

आज उप्र के तराई क्षेत्र में बसा लखीमपुर-खीरी सुर्खियों में है । 3 अक्टूबर की दोपहर सत्ता के मद में डूबे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी के हत्यारे बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी थार गाड़ी के पहियों के नीचे चार किसानों व एक पत्रकार को कुचल दिया । ये चार किसान थे गुरुविंदर सिंह , नक्षत्र सिंह , लबप्रीत सिंह, दलजीत सिंह व पत्रकार रमन कश्यप । किसानों का नेतृत्व कर रहे तेजिन्दर सिंह विर्क हत्यारों के निशाने पर थे जो इस कांड में बुरी तरह घायल हो गये ।

किसान उप्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन का विरोध करने काले झंडे लेकर हैलिपैड पर एकत्र हुए थे । किसानों का गुस्सा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के उस भाषण को लेकर था जो उसने 25 सितंबर को एक सभा में देते हुए धमकी भरे अंदाज में किसानों को टारगेट करते हुए दिया था कि यदि वह अपने पर आ जायेगा तो दो मिनट में पलिया छोड़ना पड़ेगा । उपमुख्यमंत्री ने जब आने का रास्ता बदल दिया तो यह तिकोनिया से वापस घरों को किसान लौट रहे थे कि हूटर बजाती गाड़ियों के काफिले ने उन्हें को कुचलना शुरू कर दिया । प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहली गाड़ी आशीष मिश्रा चला रहा था ।इस जघन्य हत्याकांड के वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं । इस नरसंहार ने पूरे देश में गुस्से का उबाल ला दिया और चार अक्टूबर की दोपहर तक हजारों की संख्या में किसान घटनास्थल तिकोनिया में एकत्र हो गये। किसान आंदोलन और जन आक्रोश के दबाव को देखते हुए योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया किन्तु मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर समन चस्पा करते रहे और उधर उसका बाप गृह राज्य मंत्री अमित शाह , योगी आदित्यनाथ से मिलता रहा । इधर पुलिस गृह राज्य मंत्री को सलाम ठोंकती रही तो ऐसे में हत्यारे की गिरफ्तारी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी । योगी सरकार अपना इतिहास दोहरा रही थी चाहे वह बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर हाथरस कांड के बलात्कारी ठाकुर हों , सरकार रसूखदार आरोपियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है । इस नरसंहार के साथ भी यही दोहराया जा रहा है । पूरे देश में थू थू होने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी 10 अक्टूबर को हुई किन्तु पिता के गृह राज्यमंत्री रहते हुए पुलिस की पूछताछ भी संदेह के दायरे में है ।

3 अक्टूबर के बाद से ही लखीमपुर नरसंहार को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे । दिनांक 12 अक्टूबर को शहीद किसानों व घटना में मारे गये पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए घटनास्थल के पास ही खेतों में विशाल पंडाल में अंतिम अरदास का कार्यक्रम रखा गया था । एडवा उप्र का प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रदेश सचिव सीमा कटियार , प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह व मधु गर्ग तथा मालती यादव शामिल थीं , वे भी अंतिम अरदास में हिस्सेदारी करने तिकोनिया लखीमपुर पहुंचीं थीं ।

लखनऊ से तिकोनिया के रास्ते में भारी पुलिस बल तैनात था जो हर गुजरने वाली गाड़ी से पूछताछ कर रहा था । जैसे ही हम पलिया रोड पर आये तो हमें किसानों व ग्रामीण वासियों के जत्थे के जत्थे घटना स्थल पर जाते हुए दिखने लगे थे जो पूरे रास्ते अजय मिश्रा व उसके हत्यारे बेटे आशीष मिश्रा की बड़ी बड़ी होर्डिंग को चुनौती देते हुए लग रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर भी अद्भुत दृश्य था जहां पहुंचने वाला हर रास्ता हजारों लोगों की मौजूदगी की गवाही दे रहा था । वहां हो रहे हर भाषण से मोदी योगी और काले कृषि कानूनों के लिए गुस्सा दिख रहा था ।सभी वक्ताओं की एक ही मांग थी कि अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए नहीं तो शहीदों को इंसाफ नहीं मिल सकता ।

मंच प्रबंधन को संभाल रहे गुरुबाल सिंह आजाद से एडवा ने बातचीत की तो लखीमपुर तराई क्षेत्र में सिक्ख समुदाय के बसने की कहानी पता लगी । उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जब सिक्ख परिवार अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आये तो तराई क्षेत्र में सिक्खों को मुवाअजे के तौर पर जमीनें दी गई । ये जमीन बंजर थीं जिसे सिक्खों ने अपनी मेहनत से इतना उपजाऊ बनाया । धीरे धीरे पंजाब से भी बड़ी संख्या में सिक्खों ने यहां जमीनें खरीदीं और लखीमपुर-खीरी को उप्र का सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र बना दिया । गन्ने की बड़ी खेती के कारण इस जनपद को ष्चीनी का कटोरा ष् भी कहा जाता है । तिकोनिया बनवारी पुर में रहने वाला अजय मिश्रा उर्फ टैनी महाराज ने इस क्षेत्र में आतंक फैला रखा है । उसने हिन्दुओं और सिक्खों के बीच भी नफरत के बीज बोये हैं । उसका कहना है कि वह इन सरदारों को भगाकर हिंदुओं को उनकी जमीन पर कब्जा दिलवायेगा । वह अक्सर भड़काऊ भाषण देता रहता था ।

कार्यक्रम स्थल पर हमारी मुलाकात स्वर्ण सिंह से हुई जो चैकड़ फार्म के रहने वाले थे और जिनका 18 वर्षीय बेटा प्रभजोत सिंह भी 3 अक्टूबर को आशीष सिंह की गाड़ी के नीचे आते आते बच गया था। वह मृतक लबप्रीत सिंह के साथ उस दिन प्रदर्शन में हिस्सेदारी करने आया था और गाड़ी के धक्के से किनारे गिर गया था । उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी । स्वर्ण सिंह ने बताया कि 20लोगों से भी ज्यादा लोग इस नरसंहार में घायल हुए हैं और यह भी बताया कि

घायल लोगों में कुछ लोग अजय मिश्रा से इतना आतंकित हैं कि वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से भी डर रहे हैं। उन्होंने अजय मिश्रा व उसके बेटे आशीष उर्फ मोनू के आंतक की कहानी बयान करते हुए बताया कि अजय मिश्रा के गांव बनवारी पुर और आसपास के क्षेत्र में बाप बेटे का आतंक है । उनके खिलाफ यदि कोई मुंह खोलता है तो उसे वे सबक सिखाते हैं , घर ले जाकर मारपीट करते हैं । अजय मिश्रा के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं किन्तु पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती । अब पिता के सांसद व गृह राज्य मंत्री बनने के बाद बेटा आशीष मिश्रा अपना दरबार लगाता है और गांव के जमीन जायदाद के झगडे निपटाता है । बनवारी पुर में मिश्रा परिवार का ही फरमान चलता है । किसान आंदोलन व तराई क्षेत्र के किसानों की उसमें बढ़-चढ़कर हो रही भागीदारी से मिश्रा बाप बेटे काफी बौखलाये हुए थे । गाड़ियों के काफिलों से किसानों को कुचलना उनकी किसानों के लिए उनकी नफरत को दिखाता है।

एडवा के प्रतिनिधिमंडल ने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की । पत्रकार रमन कश्यप के घर पर उनके दादा जी व भाई से मुलाकात की । रमन के भाई संदीप कश्यप ने उस दिन की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि रमन भैय्या पास के एक स्कूल में पढ़ाते थे और कुछ समय से पार्ट टाइम पत्रकारिता भी करने लगे थे । 3 अक्टूबर को रविवार था इसलिए पड़ोस में रहने वाले पत्रकार योगेश दीक्षित के साथ प्रदर्शन कवर करने चले गये । परिवार का कहना था कि उन्होंने घटनास्थल पर किसानों की मौत की खबर मिली तो रमन की जानकारी करने के लिए तमाम परिचितों के यहां फोन किए किंतु कुछ पता नहीं लग रहा था । पुलिस स्टेशन पर भी सूचना दे दी । रात के 3.30 पर पुलिस ने का फोन आया और परिवार को मा ॅरचरी में बुलाया ।भाई ने बताया कि उन्होंने देखा कि रमन का शव जमीन पर पड़ा हुआ था । रमन की शर्ट फटी हुई थी और हाथों पर तारकोल लगा था । सड़क की गिट्टी हाथ में घुस गई थी ।देखकर ही लग रहा था कि रमन को गाड़ी ने कुछ दूर घसीटा भी था । पुलिस और आरोपियों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाई कि रमन कश्यप को किसानों ने पीट पीट कर मार दिया किन्तु उनकी अफवाहों को घर वालों ने खारिज कर दिया । रमन के दो बच्चे क्रमशः 4 साल व 10 साल के हैं । एक नौजवान पत्रकार रमन कश्यप आशीष मिश्रा जैसे भाजपाइयों की गुंडई का शिकार हो गया था ।

एडवा प्रतिनिधिमंडल ने फिर लखीमपुर से लगभग 90 किमी की दूरी पर चैखड़ फार्म पर रहने वाले लबप्रीत सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की । गन्ने के खेतों में बने मकान में तमाम लोगों की मौजूदगी के बावजूद मौत का सन्नाटा छाया हुआ था ।हमारी मुलाकात सबसे पहले लबप्रीत की नानी हुई और उनसे बात कर महसूस हुआ कि घर के सबसे छोटे बेटे के न रहने पर परिवार कितना टूट गया है । ।लबप्रीत ने 12 वीं कक्षा पास की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे , वह विदेश पढ़ने जाना चाहता था । खाली समय में वह पिता सतनाम सिंह के साथ खेती में मदद करता था । कृषि कानूनों को लेकर उसमें बहुत आक्रोश था और जब किसानों के विरोध प्रदर्शन की उसे जानकारी हुई तो वह अपने दोस्त प्रभजोत के साथ जाने को तैयार हो गया ।सतनाम सिंह ने बताया कि उन्हें तिकोनिया घटनास्थल पर झगड़ा होने की खबर लगभग 4 बजे मिली तो वे फौरन वहां के लिए रवाना हो गये ।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसान हाथ में काले झंडे लेकर घर वापस आ रहे थे कि गाड़ियों का काफिला किसानों को कुचलता हुआ निकल गया । सबसे आगे वाली गाड़ी जिसे कथित तौर पर आशीष मिश्रा चला रहा था , उसके बोनट पर एक लकड़ी भी बंधी थी जो हत्या के इरादे से ही बांधी गई थी । लबप्रीत एंबुलेंस में अपने पिता से पूछता रहा कि वह बच तो जायेगा किन्तु लखीमपुर अस्पताल के नजदीक पहुंचते ही उसे खून की उल्टियां हुईं और उसकी सांसें थम गईं । सतनाम सिंह और उनकी पत्नी तथा लबप्रीत की तीनों बहनें दुख से टूट चुकी हैं । लबप्रीत का दोस्त प्रभजोत सिंह भी उस दिन उसके साथ था जिसके पिता स्वर्ण सिंह से हमारी मुलाकात अरदास कार्यक्रम में हुई थी । प्रभजोत उसी गांव में रहता है । हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उससे भी मुलाकात की ।वह उस दिन गाड़ी के धक्के से सड़क के किनारे गिरा था , उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है । डाक्टर ने उसे छरू महीने तक बिस्तर पर सीधा लेटने को बोला है । प्रभजोत ने बताया कि आंदोलन कर रहे किसानों को उपमुख्यमंत्री के रास्ता बदलकर जाने की जानकारी हुई तो वे घर वापसी के लिए लौटने लगे । वे सड़क के किनारे चल रहे थे कि अचानक गाड़ियों का हूटर सुनाई दिया और वह कुछ समझ पाता कि एक जोर का धक्का लगा और वह नीचे गिरा । उसने गिरते गिरते लबप्रीत को गाड़ी के नीचे आते देखा था । प्रभजोत ने दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है । वह पिता की खेती में मदद करता है । स्वर्ण सिंह ने एक एप्लीकेशन दिखाई जो उन्होंने पुलिस थाने पर दी है किन्तु अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है । स्पष्ट है कि पुलिस घायलों की संख्या कम दिखाने के लिए भी रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही है ।

अभी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा व अन्य आरोपी पुलिस हिरासत में हैं किन्तु आशीष का पिता अजय मिश्रा आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर विराजमान है जबकि वह पहले बयान दे रहा था कि यदि उसके बेटे के खिलाफ सबूत मिले तो वह कुर्सी छोड़ देगा और अब जब सबूत भी मिल गये हैं तो उसके आकाओं की नजर उप्र चुनावों के मद्देनजर ब्राह्मण वोटों पर टिकी हुई है ।

निश्चित रूप से किसान आंदोलन ही शहीदों को इंसाफ दिलायेगा ..

विश्व गुरू बनने चले देश के स्कूलों में शिक्षक नहीं कक्षायें भी नहीं (युनेस्को की 2021 की रिपोर्ट)

— संध्या सैली

युनेस्को की 2021 की भारत की शिक्षा केी स्थिति पर तीसरी रिपोर्ट अभी हाल में जारी हुयी। इसे 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस पर जारी किया गया। रिपोर्ट में भारत में शिक्षा की स्थिति की हालत का इस रिपोर्ट के शीर्षक से ही पता चल जाता है। ''शिक्षक नहीं - कक्षायें नहीं '' यह हमारे देश में शिक्षा की स्थिति है।

मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने यूनेस्को के दिशा निर्देश पर बनायी यह रिपोर्ट हमारे देश की शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालने वाली है। शिक्षा के अधिकार का कानून पारित करने के बावजूद इस रिपोर्ट के बाद यूनेस्को द्वारा दिये गये सुझाव इसे स्पष्ट करने के लिये काफी हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि आज भी इस देश में ग्रामीण और शहरी शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी सरकार की 2020 में पारित शिक्षा नीति की कडी आलोचना करते हुये यह रिपोर्ट कहती है कि आश्चर्य हेै कि जब सारे शिक्षा संस्थान कोरोना महामारी के चलते बंद थे तब यह नीति घोषित हुयी और इस साल उसका एक साल मना भी लिया गया।

देश के 15 लाख 51 हजार स्कूलों में 96 लाख शिक्षक हैं। इनमें पचास प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। 30 प्रतिशत से अधिक स्कूल शिक्षक उन निजी स्कूलों में हैं जिन्हे कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है। केवल 50 प्रतिशत शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं। उनमें एक लाख से अधिक स्कूल एक शिक्षक के भरोसे पर हैं। और कुल स्कूलों का 19 प्रतिशत यानि 11 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं।एक शिक्षक वाले 89 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं। और स्वाभाविक रूप से इन स्कूलों में किसी भी प्रकार की सुविधाओं के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। ये स्कूल अधिकतर अरूणाचल प्रदेश,गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश ओर राजस्थान में हैं। इसमें सबसे अधिक 21,077 स्कूल मध्य प्रदेश में, 17,683 स्कूल उत्तर प्रदेश में, 10,674 राजस्थान, तेलंगाना के 6678 और 6200 झारखंड में हैं। लेकिन राज्य में कुल स्कूलों की संख्या से इन स्कूलों की तुलना करें तो जहां मध्य प्रदेश के ये स्कूल कुल स्कूलों को 14 प्रतिशत हैं वहीं तेलंगाना के 16 प्रतिशत और झारंखड के 14 प्रतिशत हैं। इन सभी में 90 प्रतिशत से अधिक स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं। केवल 64 प्रतिशत ग्रामीण और 84 प्रतिशत शहरी स्कूलों में सारी क्लासों के लिये अलग अलग कमरे हैं।

इस पूरी स्थिति वाले देश के मुकाबले केरल एकदम अलग दिखायी देता है जहां पर 88 प्रतिशत स्कूलों में जिसमें 80 प्रतिशत ग्रामीण स्कूल भी शामिल हैं इंटरनेट की सुविधा है, लाइब्रेरी है, 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में मुफ्त किताबों का वितरण होता है। यहां पर 99 प्रतिशत में साफ पीने के पानी की सुविधा है, 98 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिये अलग शौचालय है और 99 प्रतिशत स्कूलों में अबाध बिजली की सुविधा है। हिंदी पट्टी के प्रदेशों में अलबत्ता स्थिति बेहद खराब है। मध्य प्रदेश मे ंतो केवल 55 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 66 प्रतिशत और राजस्थान में 74 प्रतिशत स्कूलों में बिजली है। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली भाजपा के द्वारा शासित प्रदेशों के स्कूलों में इंटरनेट की स्थिति उनमें बिजली की उपलब्धता से देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के केवल 11 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस देश में प्राथमिक शिक्षा चुंकि राजनैतिक एजेंडे पर नहीं है इसलिये आज भी दुनियां में सबसे अधिक युवा जनसंख्या का देश अशिक्षा और बदतर शिक्षा से जूझ रहा है। जहां में धार्मिक पहचान और धर्म जनता के लिये और सरकार के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो उस देश में इंडिया स्किल रिपोर्ट की हाल में प्रकाशित आठवीं रिपोर्ट के अनुसार यदि 50 प्रतिशत से अधिक ग्रेजुयेट नौकरी करने लायक न हों तो आश्चर्य नहीं है। युनेस्को की इस रिपोर्ट को यदि भारत सरकार अपने स्थाई विकास लक्ष्य 2030 को पूरा करने के लिये आधार माने तो देश की शिक्षा की स्थिति सुधर सकती है।

लेकिन शिक्षा यह इस सरकार के एजेंडे पर ही नही है। बल्कि अंतर्राष्टीय स्रत के शिक्षण संस्थानों को कैसे मटियामेट किया जा सकता है और पिछड़ी मानसिकता, झूठा इतिहास कैसे बच्चों के दिमागों में भर कर उन्हे विषाक्त किया जा सकता है यही इस सरकार का एजेंडा है। इसीलिये स्थाई विकास लक्ष्य 2030 के चैथे क्रमांक के शिक्षा से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये यह सरकार कुछ करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।

संयुक्त राष्ट ने पोस्ट कोविड 19 शिक्षा की स्थिति का आंकलन करने के लिये वैश्विक शिक्षा से संबंधित एक विशेष बैठक की जिसके बाद जारी एक बयान के अनुसार कोविड महामारी ने पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 20 साल में हासिल उपलब्धियों को मिटा दिया है। दुनियां भर में 10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त बच्चे न्यूनतम पढने लिखने से अक्षम हो गये हैं। हम समझ सकते हैं कि जब दुनियां की बात हो रही है तो कोविड के दौरान इंटरनेट के माध्यम से हो रही पढाई से भारत के कितने विद्यार्थी पढ पाते होंगे इसे भी इस रिपोर्ट में सामने लाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण भागों में केवल 18 प्ररतिशत के पास इंटरनेट की सुविधा थी लेकिन उसमें भी कितने इसका उपयोग कर पाये इसकी शंका है क्योंकि डाटा पैक खरीदने के लिये पैसा होना, मोबाइल चार्ज करने के लिये बिजली का होना जैसे प्रश्न इससे जुडे हुये हैं। शहरी क्षेत्र में 42 प्रतिशत के पास इंटरनेट की सुविधा है ऐसा रिपोर्ट बताती है लेकिन शहरी गरीब बस्तियों में रहने वाले कितने छात्र छात्रायें इसका लाभ उठा पाये यह एक सवाल है।

इसके अलावा रिपोर्ट यह भी बताती है कि निजी स्कूलों में हायर सेंकेंडरी स्तर के प्रायवेट स्कूलों में 62 प्रतिशत से अधिक शिक्षक कम योग्यता वाले हैं। ऐसे में यद्यपि शिक्षकों ने अपनी क्षमता भर काम करने की कोशिश की लेकिन इसमें वे कितना सफल हुये होंगे यह आने वाला समय ही बतायेगा। रिपोर्ट ने अंत में दस सुझाव भी दिये हैं जिससे हम देश में गुणत्तापूर्ण और सबके लिये शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख स्कूलों में उत्तर पूर्वी ओर ग्रमीण इलाकें के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।

कुल मिला कर स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करना, अधिक से अधिक सरकारी क्षेत्र में स्कूल खोलना जिससे फीस आदि की वजह से गरीब और ग्रामीण बच्चे शिक्षा से महरूम न रह सकें और शिक्षक छात्र अनुपात को कम करना यानि स्कूलों की संख्या बढाना शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में और स्थाई विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण पहलकदमी हो सकती है। लेकिन क्या हमारे देश की सरकार यह सब करने के लिये तैयार है???

कोरोना वैक्सीन कैम्प की आवश्यकता और उसके अनुभव

— नीलम तिवारी

(वैक्सीनेशन की आनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मलिन बस्तियों मे रहने वाली महिलाओ के लिए एक कठिन समस्या है। ऐसी स्थिति में एडवा की उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की इकाई ने पहल करके गरीब बस्तियों में वैक्सिनेशन कैंप लगाने की शुरूवात की। कानपुर की एडवा की कार्यकर्ता नीलम तिवारी ने इस संबंध में अपने अनुभव न्यूज़ लेटर के साथ साझा किये - संपादक)

कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से ही वैक्सीनेशन की आवश्यकता को अधिकतर लोगों ने गम्भीरता से समझना शुरू कर दिया है। मेरे घर मे काम करने वाली महिला ने बड़ी मायूसी से मुझे बताया कि दीदी हमें और हमारे पति को वैक्सीन लगवाना है लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के हो नही पा रहा है। कल एक जगह गये थे काफी देर लाइन मे लगे रहे धूप और गर्मी के मारे बेहाल हो गये और जब नम्बर आया तो हमसे कहा गया कि यहां पर केवल रजिस्ट्रेशन वालों को ही वैक्सीन लगेगी और हमे लौटा दिया गया अब हम क्या करें। जहां हम काम करते है सबने कहा है पहले वैक्सीन लगवा कर आओ तब काम करवायेंगे हमारे आदमी से उसके मालिक ने वैक्सीन का सर्टीफिकेट मांगा है अगर वैक्सीन नही लगवायेंगे तो काम नहीं मिलेगा हम लोग बहुत परेशान है दीदी कुछ करो।

उनकी परेशानी देख कर मुझे इस सरकार की ब्यवस्था पर बहुत गुस्सा आया फिर सोचा अपनी महिलाओ के लिए हमे ही प्रयत्न करके इस काम को करवाना पड़ेगा। मेरे पास एक स्वास्थ्य कर्मी का फोन नंबर था जो पास के सामुदायिक केंद्र मे कार्यरत है। मैने उस महिला को अपने संगठन का परिचय देते हुए वैक्सीन से सम्बंधित समस्या के विषय मे बताया उस महिला स्वास्थ्य कर्मी ने सामुदायिक केंद्र मे बैठने वाली डाक्टर से मेरी बात करवायी ।मैने उन महिला डाक्टर को भी विस्तार से महिलाओ के वैक्सीनेशन की समस्या के विषय मे बताया उन्होने हमारे संगठन के बारे मे विस्तार से जानकारी पूछी तब मैने उन्हे एडवा की संस्थापक सदस्य डाक्टर कैप्टन लक्ष्मीसहगल और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली का परिचय देते हुए संगठन के द्वारा किए जाने वाले कामों की विस्तार से जानकारी दी। डाक्टर बहुत खुश हुई मेरे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हो गयी और उन्होने पूरी तरह से सहयोग करने के लिए कहा। डाक्टर अंजली द्विवेदी जो कि कानपुर जिले के सरकारी अस्पताल मे कार्यरत है उन्होने कहा आप अपने लेटर पैड पर एक प्रार्थनापत्र लिखिए और अपने लेटर पैड पर महिलाओ की लिस्ट बनाकर मुझे भेज दीजिए मै डी आई ओ आफिस से अनुमति लेकर आपके क्षेत्र मे कैम्प की ब्यवस्था करवाती हूं।बस फिर मैने महिलाओ की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया और काम शुरू हो गया।

मैने सभी महिलाओ को महिला समिति का मेम्बर बनाया और उन्हे समझाया कि यह काम हम अपने संगठन की वजह से कर पा रहे हैं। ऐसा करने से हम महिलाओ के उस प्रश्न का जवाब दे पाये जो हमसे अक्सर किया जाता है कि दीदी आपका मेम्बर बने से हमका का मिली? पहले

कैम्प मे 67 महिलाओ का सफल टीकाकरण हुआ अब और महिलाएं आयी फिर दूसरे कैम्प के लिए लिस्ट बनानी शुरू की इस बार 122 लोगों को वैक्सिनेशन एडवा कानपुर ने अपनी देख रेख में करवाया। अब तक समझ मे आ गया था कि यह काम सभी यूनिटों मे कैसे करवाना है। पूरे कानपुर जिले मे जहां जहां एडवा की यूनिट है हमने अपने लेटर पैड पर प्रार्थनापत्र लिख कर अनुमति लेकर अलग अलग यूनिटों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। जैसे अनुमति मिलती गयी हमारे कैम्प हमारी कार्यकर्ताओं की देख रेख में लगने शुरू हो गये। कहीं कहीं महिलाओ की संख्या अधिक होने पर सुरक्षा के लिए हमे पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगनी पड़ी। वर्तमान समय मे जब मै अपना अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूं लगभग 600 महिलाओ का वैक्सिनेशन कानपुर के अंदर एडवा द्वारा करवाया गया है अभी आगे और यूनिटों मे लिस्ट बनायी जा रही है यह संख्या और अधिक बढ़ेगी। मेरा अनुभव यह रहा कि इस तरह के कामों से हमारे संगठन के प्रति हमारे महिला सदस्यों का भरोसा भी मजबूत हुआ और सदस्यता करने मे आसानी हुई। यह सभी सदस्य आगे आन्दोलन से भी जुड़ेंगे और हमारे संगठन को मजबूत बनायेंगे। भविष्य मे हमे इसी तरह के कदम उठाने होंगे अपने संगठन को जिन्दा रखने के लिये।

भाजपा शासित असम सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की शैतानी साजिश

असम में जबरन बेदखली के दौरान राज्य पुलिस की फायरिंग से दो किसानों की मौत हो गई जिनमें से एक 12 साल का लड़का था। 24 सितंबर 2021 को हुयी यह पुलिस फायरिंग न केवल निंदनीय बल्कि भत्र्सना योग्य है। जिला प्रशासन द्वारा किराए पर लिए गए पेशेवर फोटोग्राफर बिजय शंकर बनिया का स्तब्ध कर देने वाला वीडियो पूरे देश में देखा गया है, जो पुलिस की गोली सीने पर लगने से जमीन पर पड़े व्यक्ति को लात और घूंसे मार रहा है । पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। असम की घटनाओं से एक बार फिर साबित होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर रखना घृणा की राजनीति के केंद्र में हैं जिसकी मुख्य प्रचारक भाजपा है जिसका लक्ष्य इस देश की जनता का धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करना है।

असम की इस घटना के ठीक 10 दिन बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को एक और खौफनाक घटना सामने आई, जिसमें भाजपा की नफरत की राजनीति को दिखाया गया। भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से संबंधित कारों के काफिले ने जिसमें एक कार उनका बेटा आशीष मिश्रा टेनी चला रहा था, प्रदर्शन केबाद शांतिपूर्वक लौट रहे चार सिख किसानों को रौंद दिया और कई अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया । यह सीधे सीधे हिंदू-सिख विभाजन को तेज करने की स्पष्ट कोशिश थी। क्योंकि वहां पर उपस्थित एक पत्रकार को भी जो संयोग से हिंदू था, भाजपा के इन राक्षसों ने रौंद दिया। और उसके बाद उस पत्रकार की हत्या का आरोप सिख किसानों पर लगाने की बेशर्म कोशिश की। इस नरसंहार की निंदा करते हुए पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे । आज हालांकि इस नरसंहार के बाद एक महीने बीत चुके हैं, लेकिन भाजपा के मंत्री अभी भी अपने पद पर मौजूद हैं और उन्हें इस बर्बर और बेरहम हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है।

आरएसएस-भाजपा अपनी स्थापना के बाद से ही इस नफरत की राजनीति में लिप्त रहे हैं। इससे पूरे देश में असंख्य सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिससे हजारों निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। सभी देशभक्तों को आरएसएस और भाजपा का सीधे सीधे सामना करने के लिये तैयार होना ही होगा।

एडवा ने एकजुटता दर्शाते हुये एक टीम को आसाम में उस इलाके में भेजा जहां पर जबरिया बेदखली और पुलिस के द्वारा हत्यायें की गयी थीं। एडवा ने इन क्षेत्रों में संकट में पड़े लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की मदद करने का संकल्प लिया है । हम यहां हमारी टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दे रहे हैं।
- मरियम धवले,एडवा महासचिव

एडवा की केंद्रीय टीम जिसमें सहायक सचिव नियति बर्मन, संयुक्त सचिव कनिका घोष, सीईसी सदस्य सोमा दास, असम की सहायक सचिव अनु रिजल और पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय सदस्य बिल्किस बेगम शामिल थी ने 6 अक्टूबर, 2021 को धोलपुर क्षेत्र का दौरा किया जहां असम राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को जबरन बेदखल कर दिया गया था और उस कार्यवाही के दौरान हुयी पुलिस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने सूरातुली, तिरकरा, धालपुर, खानुआ और गरुखुटी इन सारे गांवों से लोगों को बेदखल करने का फैसला किया था। धोलपुर क्षेत्र ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ है। किरता गोरेश्वर में भी बेदखली की गई. यह पूरी बेदखली गरूखुटी कृषि फार्म शुरू करने के बहाने की गई। टीम ने प्रभावित परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं से मुलाकात की और अधिकारियों द्वारा दिखाई गई क्रूरता और संवेदनहीनता का विवरण सुनकर टीम के सदस्य हैरान रह गये। महिलाओं ने उन पर बरपायी गयी तबाही के हृदयविदारक विवरण दिए जो इस बेदखली ने उनके जीवन में पैदा कर दी हैं ।

हम मालीगांव बुर्राबाजार से कार से निकले और एक छोटे से झरने को पार करते हुये निस्सालमिरा पहुंचे, जहां मुसलमानों और हिंदुओं की मिश्रित आबादी है। वे मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के रहते हैं । लेकिन भाजपा-आरएसएस उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

हजारों लोगों को निर्दयता से बेदखल कर रातोंरात बेघर कर दिया गया । पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में दो किसानों की मौत हो गई। इनमें से एक 12 साल का लड़का था। बेघर लोग अब एक दम खुले आसमान के नीचे या तो भारी बारिश में या धधकते सूरज का सामना करते हुये रह रहे हैं । महिलाएं तो सबसे असुरक्षित और दयनीय स्थिति में जी रही हैं। वे कुछ अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। उनके पास भोजन, पीने के पानी और साफ सफाई भी नहीं हैं । वे नदी के पानी का हर काम के लिये सीधे उपयोग कर रहे हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए स्थिति विशेष रूप से दुखद है क्योंकि वे उसी नदी के पानी का उपयोग धोने के उद्देश्य से

करती हैं। बच्चों और बूढ़े लोगों का स्वास्थ्य खतरे में हैं । स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण की अनुपलब्धता के कारण गर्भवती महिलाएं बहुत असुरक्षित स्थिति में हैं । नजदीकी अस्पताल में सफर करना अब उनके लिए काफी मुश्किल है। महिलाएं और बच्चे अपनी अनकही पीड़ा सुनाते समय अपने आंसुओं को नहीं रोक पाये।

जब हमने उनसे कहा कि हम एक महिला संगठन से हैं और न्याय के लिए उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं तो उन्होने तुरंत हमें घेर लिया, विशेष रूप से महिलाओं ने जो अपने आंसू नहीं रोक पायीं। अक्तुनिसा, जुबेदा, अनवरा बेगम और अन्य ने हमें बताया कि उन्हे वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया और न ही सरकार ने उन्हें पुनर्वास के कोई अवसर प्रदान किए। बिना किसी चेतावनी के उनका सामान फेंक दिया गया। महिलायें यह समझने में विफल थीं कि क्यों उनकी इस तबाही के लिये खुद उनके द्वारा चुनी गयी सरकार जिम्मेदार है। इस क्षेत्र में उनकी 10 आंगनबाड़ियों और राशन की दुकानें थीं। सरकार की कई परियोजनाएं यहां लागू की गई हैं। फिर भी उन्हें अवैध निवासी घोषित किया गया और उन्हें बेदखल कर दिया गया । यहां तक कि उनके कब्रिस्तानों को भी नहीं बख्शा गया। उनकी आंगनबाड़ियों और मदरसों को सभी नष्ट कर दिया गया है। बच्चे आंगनबाड़ियों में जाते थे क्योंकि महामारी के कारण मदरसे बंद हो गये थे .इन आंगनबाड़ियों के नष्ट होने के बाद बच्चे बस यहां-वहां बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे हैं। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का जो भी कम अवसर मिला था, वह अब छीन लिया गया है।

मेहजबीन नाम की एक महिला ने कहा कि सरकार इतनी बेरहम है कि उसने बच्चों की परवाह भी नहीं की हालांकि उनके पास उचित कागजात और दस्तावेज हैं। एक मुस्लिम महिला (जिसने अपना नाम नहीं बताया)ने हमें बताया कि उनके जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से उन्हे बेदखल किया गया। उनकी भूमि, खेत, आजीविका सब कुछ नष्ट कर दिया

गया जबकि वे वहां पर 50 सालों से रह रहे हैं। वहां पर रह रहे दूसरे परिवार बहुत डर और संकट में रह रहे है कि शायद उखडने की अब उनकी बारी हो सकती है।

हमने बाइक पर आगे बढ़ने शुरू किया और मीलों दूर तक जेसीबी मशीनों द्वारा नष्ट की गई और ट्रैक्टरों द्वारा खोद दी गयी जमीन देखी । सड़क पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और गढढो से भरी थी। हमारी मोटरसाइकलों को चलाने वाले युवा इसी इलाके में काम कर चुके थे। उन्होंने हमें दिखाया कि जहां पर वे बैठ कर गप्पे करते थे, जहां पर चाय की दुकाने हुआ करती थीं वहां पर मीलों तक खाली पन है। कहीं कहीं पर लोहे की जालियों की बाड़ें टूटी हुयी दिखती हैं जो वहां पर रह चुके इन्सानों की बस्तियों की एक मात्र निशानी है।

खेतों में, वे लौकी, गोभी और फूलगोभी उगाते थे। इससे स्थानीय बाजार में सस्ती दरों पर सब्जियां उपलब्ध कराने में मदद मिलतीी थी। उन खेतों पर अब पानी भर गया है। महिलाओं ने हमें बताया कि अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं।

हमारी टीम ने पाया कि बेदखल किए गए परिवार इस जगह के कानूनी निवासी हैं। महिलाओं ने हमें अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के साथ ही जमीन के कागजात दिखाए। हम कुछ पुराने लोगों से मिले जिन्होंने बताया कि वे 1970 से इस जगह पर रह रहे हैं। हालांकि वे कानूनी मतदाता हैं, लेकिन उनके खिलाफ लगातार और सुनियोजित तरीके से नफरत फैलाने वाला अभियान चल रहा है कि वे संदिग्ध नागरिक और अवैध अतिक्रमण करने वाले हैं। उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान हैं। प्रशासन ने इन्हें बेदखल कर ली गई जमीन पर खेती शुरू कर दी है और लोगों को वहां पहुंचने से रोकने के लिए इन इलाकों के आसपास रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं।

हम दो और किलोमीटर का सफर तय कर मैनुल हक के घर पहुंचे। पुलिस की फायरिंग में उसकी मौत हो गई। उनकी विधवा अपने दो बेटों मकसिदुल और मुकददस अली और बेटी मनसुरा बेगम के सामने अपने आंसू नहीं रोक सकीं । वह उस दिन की उन दर्दनाक यादों को नहीं भूल सकती, जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी । मैनुल की न केवल गोली मारकर हत्या कर दी गई बल्कि एक पत्रकार ने छलांग लगाकर उसके मृत शरीर पर हमला कर दिया जबकि पुलिस चुपचाप देखते हुये खड़ी थी। इस बर्बरता को पुलिस नेे नहीं रोका। उसके ससुर मकबूल अली सदमे की हालत में थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि हमसे बात करनी है या अपने पोते-पोतियों के आंसू पोंछना है या भोजन सामग्री इकट्ठा करनी है । बिना किसी कमाई के वे अपना खाना हासिल करने में नाकाम हैं । इन लोगों को तब तक भोजन नहीं मिलता जब तक कि कोई आकर उन्हें मदद उपलब्ध नहीं कराता।

युवक ने भी इसी त्रासदी और लाचारी कोसुनाया । एक बुजुर्ग व्यक्ति (जिन्होने अपना नहीं बताया) ने बताया कि वह पिछले 70 साल से वहां पर रह रहा है। उसके पास सभी उचित दस्तावेज, वोटर आईडी, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, फिर भी उसे बेदखल कर दिया गया है । उस व्यक्ति ने प्रण लिया है कि अपने अधिकारों के लिए अंत तक संघर्ष किया जायेगा ।

दो बाइकर्स ने हमें बताया कि यहां पर आने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडल को इन जगहों पर ले जाने पर उनके साथ मारपीट की गई । हम उस स्थान पर जाना चाहते थे जहां उन्हें पीटा गया था लेकिन उन्होंने हमें यह कहते हुए रोक दिया कि इससे उन्हें और अधिक समस्याएं होंगी । यह मौजूदा आतंक की स्थिति है!

एडवा असम राज्य और जिला समितियों ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर अमानवीय बेदखली पर तत्काल रोक लगाने, बेदखल किए गए परिवारों को उचित मुआवजा और उनके पुनर्वास और 24 सितंबर 2021 को धोलपुर और गारूखुटी क्षेत्रों में हुई गोलीबारी की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है ।

बेदखली के बाद से प्रशासन ने अब तक कोई मदद नहीं दी है । महिलायें अपने जीवनयापन के साधन नहीं ढूंढ पा रही हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी काफी चिंतित हैं। निराशा में उन्होंने कहा, ''अब हम क्या करें ? हम भारतीय नागरिक हैं। लेकिन हमारी अपनी सरकार ने हमारे साथ ही दुश्मन के तरीके से व्यवहार किया है!

भाजपा-आरएसएस द्वारा की जा रही घृणा की सांप्रदायिक, फासीवादी राजनीति के खिलाफ एडवा अभियान चलाएगी । भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर इस संघर्ष को आगे ले जाना होगा।